(ग) 1991–92 तथा 1992–93 के वर्षों के दौरान इन केन्द्री को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मुकुल वासनिक) (क) उत्तर प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या 58 हैं।

(ख) नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हुई है:–

(i) संरक्षण और पुनसृजन द्वारा सौहार्दपूर्ण सहभागिता के जरिये युवाओं का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा व्यक्तित्व संबंधी विकास।

(ii) गैर-छात्र युवाओं को सामाजिक बुराइयों, महिलाओं पर अत्याचार, मद्यपान, नशाखोरी आदि के विरूद्ध लड़ने के लिये तैयार करना।

(iii) ब्लाक और जिला स्तर पर युवा कल्बों का आयोजन, सामुदायिक कार्य शिविरों के लिये समूह कार्यकलाप, प्रजातंत्र नेतृत्व का विकास तथा उनम भावात्मक सहभागिता तथा राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा करना।

(iv) गैर छात्र युवा की विशाल असंगठित शक्ति को संगठित करना ताकि उनकी शक्ति और वैयक्तित्व को समाज के लाभ के लिये प्रयोग किया जा सके और उन्हें कार्यात्मक तौर पर कुशल, आर्थिक तौर पर उत्पादी और आध्यात्मक व चरित्र के प्रति जागरूक नागरिक बनाया जा सके।

(ग) वर्ष 1991–92 तथा 1992–93 के दौरान उत्तर प्रदश में स्थिति नेहरू युवा केन्द्रों को निम्नलिखित धनराशि दी गई थी।

वर्ष	दी गई धनराशि
	रुपये
1991–92	73,07,475.00
1992–93 (फरवरी 1993 तक)	90,33,510.00

Action Plan to Stop Voilence against Women

@582. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have prepared an action plan to stop the rising incidence of violence against women; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): No, Sir.

(b) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति का असंतोषजनक होना

583. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति असंतोषजनक है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

@Previously Unstarred Question 284, transferred from 24-2-1993.

(ग) पिछले तीन वर्षों में क्या लक्ष्य रखे गये और इनकी उपलब्धि क्या रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) दक्षिण के राज्यों की तुलना में समस्त हिन्दी भाषी क्षेत्रों में पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही है । उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति सभी हिन्दी राज्यों के समान ही है ।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम जो इससे पूर्व प्रमुख कार्यनीति थी, को धीरे-धीरे हटा कर पूर्ण साक्षरता अभियान को प्रमुख कार्य नीति के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया था । बीच के वर्षों में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम की परियोजनाओं को पूरी तरह से बन्द करके अभियान दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई थी, जिसके कारण कार्यक्रम की गति तथा प्रगति में गिरावट आ गई । उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक परियोजनाओं को प्रशासनिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये । तथापि, अब तक राज्य के आठ जिलों अर्थात् फतेहपुर, चमोली, देहरादून, अल्मोड़ा, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा बिजनौर में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किये गये हैं : 12 और जिलों के भी प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

Transfer of surplus Teachers in Kendriya Vidyalayas

584. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 550 teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan have been rendered surplus;

(b) if so, number of such teachers, category-wise and region-wise;

(c) whether AIKVTA has challenged the basis of their being declared SURPLUS; and

(d) if so, the reaction of the Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (d) The Kendriya Vidyalaya Sangathan has an overall shortage of regular teachers and as such the question of declaring any teacher as "SURPLUS" to the organisation does not arise. However, in any particular academic year, the number of teachers in a specific school could be in excess of the sanctioned strength for short intervals of time for various reasons, such as reduction in staff strength due to decrease in number of sections, promotions, transfers and delays in joining new positions. Adjusting the number of teachers in any particular school through inter-regional and intra-regional transfers, and by reallocation of costs amongst schools according to emerging needs is a continuing process.

गुजरात में आपरेशन "ब्लैक-बोर्ड"

585. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में "आपरेशन ब्लैक-बोर्ड" के अन्तर्गत कितने अध्ययन केन्द्रों का निर्माण किया गया है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत और धन-राशि दिए जाने की मांग की है;